



संपादक सीमा गुप्ता

चुनाव के पहले आयुक्तों की नियुक्ति

देश में आम चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गए हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को पूरी तरह तैयार करने की अनिवार्यता को समझा जा सकता है। मगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जिस तरह एक औपचारिक रिवायत की तरह पूरी भर कर ली जाती है, उसमें इस संस्था को लेकर कई बार नाहक एक भ्रम वैदा हो जाता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति ने दो नए चुनाव आयुक्तों के नाम तय कर दिए हैं। इसके तहत ज्ञानेश कुमार और बलविंदर संधू नए चुनाव आयुक्त होंगे। गौरतलब है कि एक चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे फरवरी में सेवानिवृत्त हो गए थे और दूसरे असण गोयल ने हाल ही में अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नियमों के मुताबिक चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा दो चुनाव आयुक्त होते हैं। कहा जा सकता है कि नए कानून के तहत ये पहली नियुक्तियां होंगी। इससे पहले सरकार की सिफारिश के मुताबिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती थी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक जरूरी कदम है। मगर इस क्रम में पिछले कुछ समय से जिस तरह के विवाद उठते रहे हैं, उससे देश की इस सबसे भरोसेमंद मानी जाने वाली संस्था की कार्यप्रणाली को लेकर कुछ आशंकाएं उभरी हैं। इस बार भी दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सिर्फ एक रात पहले उन्हें दो सी बारह नामों की सूची दी गई। फिर इससे संबंधित बैठक शुरू होने के महज दो मिनट पहले सरकार की ओर से उनके पास छह नाम भेजे गए: इनमें कम समय में सूचीबद्ध किए गए लोगों की ईमानदारी और तजुर्बे की जांच करना असंभव है। उन्होंने इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए समिति में प्रधान न्यायाधीश को भी रखने की बात कही। अगर विपक्ष के नेता का आरोप सही है तो इसका मतदान यह है कि सरकार की ओर से शायद चुने गए नामों को लेकर आखिरी समय तक भ्रम की स्थिति बनाए रखने की कोशिश हुई। सवाल है कि देश में लोकतंत्र को जमीन पर उतारने का बड़ा दायित्व संभालने वाली जिस संस्था का गठन पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए, उसे लेकर किसी भी स्तर पर पर्यावारी क्षेत्रों वर्ती जाती है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर पहले भी सरकार की मंशा पर सवाल उठे हैं। जरूरत इस बात की है कि आयुक्तों के नामों को सूचीबद्ध करने, उनके चयन से लेकर नियुक्ति तक के मामले में समूची प्रक्रिया सरकार पारदर्शी तरीके से पूरी कराए। अगर किसी भी पक्ष की ओर से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मसले पर वाजिब तर्कों के साथ सवाल उठाए जाते हैं, तो इससे आयोग की विश्वसनीयता कमज़ोर होगी। यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आम जनता और मतदाताओं के बीच आयोग के सदस्यों के कामकाज को लेकर कोई भ्रम न पैदा हो। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और उसकी कार्यपद्धति पर बहुत कुछ निर्भर करता है, जिससे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जीवन कायम रह सके।

पार्टी के अवैध कार्यालयों पर कारवाई

जेकेएस संचादाता

भायंदर: भायंदर पूर्व के गोल्डन नेस्ट सर्किल के पास रखे गए शिवसेना (सिंदे) के कंटेनर शाखा को शिवसेना को मनपा ने कारवाई करते हुए वहां से हटा दिया है। हालांकि इससे पूर्व ११ मार्च को प्रभाग ४ की सहायता आयुक्त तथा प्रभाग अधिकारी प्रियंका भोसले ने उक्त स्थान से कंटेनर शाखा को हटाने के लिए नोटिस भी जारी की थी। जिसमें कहा गया था कि मनपा के प्रभाग समिति ४ अंतर्गत गोल्डन नेस्ट सर्किल के पास पादचारी (फुटपाथ) सड़क पर १४ टृष्णु फुट माप की लेहे के कंटेनर के रूप में शिवसेना पार्टी का कार्यालय शुरू की गई है। इस नोटिस के प्राप्त होते ही उक्त स्थान से कंटेनर



ताकाल हटा लें, अन्यथा उसे मनपा द्वारा हटा दी जाएगी, और इस कार्य में लगने वाला खर्च कर के रूप में वसूल की जाएगी। दरअसल कंटेनर शाखा वहां से हटाने की मांग भाजपा के पूर्व विधायक ने नेट्रो भेजता ने मनपा से की थी। शिवसेना विधायक सरनाईक ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि मनपा द्वारा किए गए सर्वे में कई राजनीतिक दलों के कार्यालय अवैध पाए गए थे, अगर उन सब पर भी कारबाई होंगी तो शिवसेना भी कंटेनर शाखा हटा लेगी। आज गोल्डन नेस्ट सर्किल के पास मनपा द्वारा कारबाई किए जाने के बाद सरनाईक और भेजता ने जारी शीतयुद्ध के और गहराने के सकेत हैं।

जनकल्पण संवा

ठाणे | वर्ष - २३ | अंक - ९ | १८ से २४ मार्च २०२४ | पृष्ठ - ४ | कीमत : २ रु. | Postal Reg. No. PLG/08/2022-2024

बढ़ती आबादी को देखते हुए काशीगांव पुलिस स्टेशन का शुभारंभ

जेकेएस संचादाता

मीरा रोड। मीरा-भायंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्त के अंतर्गत नवनिर्मित काशीगांव पुलिस स्टेशन का उद्घाटन समारोह है और जिला योजना समिति पालघर के फंड से प्राप्त सरकारी वाहनों का उद्घाटन समारोह गुरुवार को संपन्न हुआ। स्थानीय लोकसभा सांसद राजन विचारे ने पुलिस आयुक्त मधुकर पाटेड्य और नवनियुक्त प्रभारी



पुलिस निरीक्षक राहुल बुमार वार्टील को बधाई दी। बता दें कि १ अक्टूबर २०२० को एमबीबीवी पुलिस आयुक्तालय

को स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री

बाद से ही आयुक्तालय अंतर्गत

कई पुलिस स्टेशन प्रस्तावित थे, उसमें से एक काशीगांव पुलिस स्टेशन थी था। सांसद विचारे ने कहा कि क्षेत्र की आबादी को देखते हुए यहां पुलिस स्टेशन की आवश्यकता थी, जिसकी मांग लोगों के द्वारा की जा रही थी। गुरुवार को उपमुख्यमंत्री द्वेष फड़नवीस द्वारा ऑनलाइन काशीगांव पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया।

आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ४९ सीट पर मतदान होगा।

छठा चरण: २५ मई को सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ५७ सीट पर मतदान होगा।

सातवां चरण: एक जून को आठ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की ५७ सीट पर मतदान होगा।

१३ राज्यों में २६ सीटों पर उपचुनाव भी होंगे राजीव कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव के साथ २१ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की १०२ सीट पर मतदान होगा।

दूसरे चरण: २६ अप्रैल को १३ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की ८९ सीट पर मतदान होगा।

तीसरा चरण: सात मई को १२ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के १४ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा।

चौथा चरण: १३ मई को १० राज्यों के ९६ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इनमें हिमाचल प्रदेश के दिन ही उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इनमें हिमाचल में सबसे अधिक छह, गुजरात में पांच और उत्तर प्रदेश में चार सीटें हैं।

देश में लोकसभा चुनाव की गुंज, ४ जून को निकलेंगे परिणाम



मुख्य चुनाव आयुक्त ने दो और सुखबीर सिंह संधू के साथ संबंधित राजीव कुमार ने बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में सभी सात चरणों में मतदान

समाजसेवा की आड में अवैध निर्माण करने वाला हिरेन पारेख

अल्केन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की फाटक रोड भाईदर पूर्व की एक्सपोर्ट कंपनी के टेरेस पर अवैध बांधकाम करके अपने समाज सेवक इमेज का बखुबी फायदा उठाते हैं हिरेन पारेख। इस मामले में बहुत सारी शिकायतें प्रभाग ४ में की गई हैं। आने वाले वक्त में अल्केन कंपनी के अवैध बांधकाम पर भी तोड़कर कर सकती है प्रभाग चाहे की सहाय्यक आयुक्त प्रियांका भोसले।



काशीमीरा पुलिस की बड़ी कामयाबी



नागरिक भ्रमित हो जाते हैं। इसके बाद वह तुरंत पुलिस के साथ मोबाइल फोन खोने की रिपोर्ट करने

पहुंचता है। थाने या ऑनलाइन

शिकायत दर्ज करने के बाद ज्यादातर फरियादियों को मोबाइल

मिलने की कोई उम्मीद नहीं रहती। दरअसल, पुलिस के लिए मोबाइल फोन दुःखा एक चुनौती है। बिहार, झारखंड, नेपाल से चोरी हुए मोबाइल फोन सीधे मिलना संभव नहीं है। इसलिए, पुलिस को तकनीकी रूप से जांच करने और लापता फोन बरामद करने में बहुत कम सफलता मिलती है। देवा गया है कि कई सामान

